

अंतरराष्ट्रीय वन दविस

प्रीलमिस के लिये:

अंतरराष्ट्रीय वन दविस, वशिव जल दविस, संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और कृषि संगठन, भारत वन स्थिति रिपीरट ।

मेन्स के लिये:

संरक्षण, वकिस से संबंघति मुद्दे, वन संसाधन, भारत के वन, राज्य और संबंघति पहलें ।

चर्चा में क्यों?

हर साल 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) द्वारा अंतरराष्ट्रीय वन दविस (International Day of Forests- IDF) के रूप में मनाया जाता है ।

- यह ध्यान देने योग्य है कि 22 मार्च के ठीक एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा वशिव जल दविस मनाया जाता है ।

प्रमुख बडि

अंतरराष्ट्रीय वन दविस:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी प्रकार के वनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दविस के रूप में घोषित किया गया ।
- वृक्षारोपण अभियान जैसे- वनों और वृक्षों को शामिल करने वाली गतिविधियों के आयोजन हेतु देशों को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।
- वन तथा कषेत्र में अन्य प्रासंगिक संगठनों पर सहयोगात्मक भागीदारी हेतु आयोजक संयुक्त राष्ट्र वन फोरम एवं सरकारों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के [खाद्य और कृषि संगठन](#) (Food and Agriculture Organisation- FAO) शामिल हैं ।
- अंतरराष्ट्रीय वन दविस 2022 की थीम "वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत" (Forests and Sustainable Production and Consumption) है ।

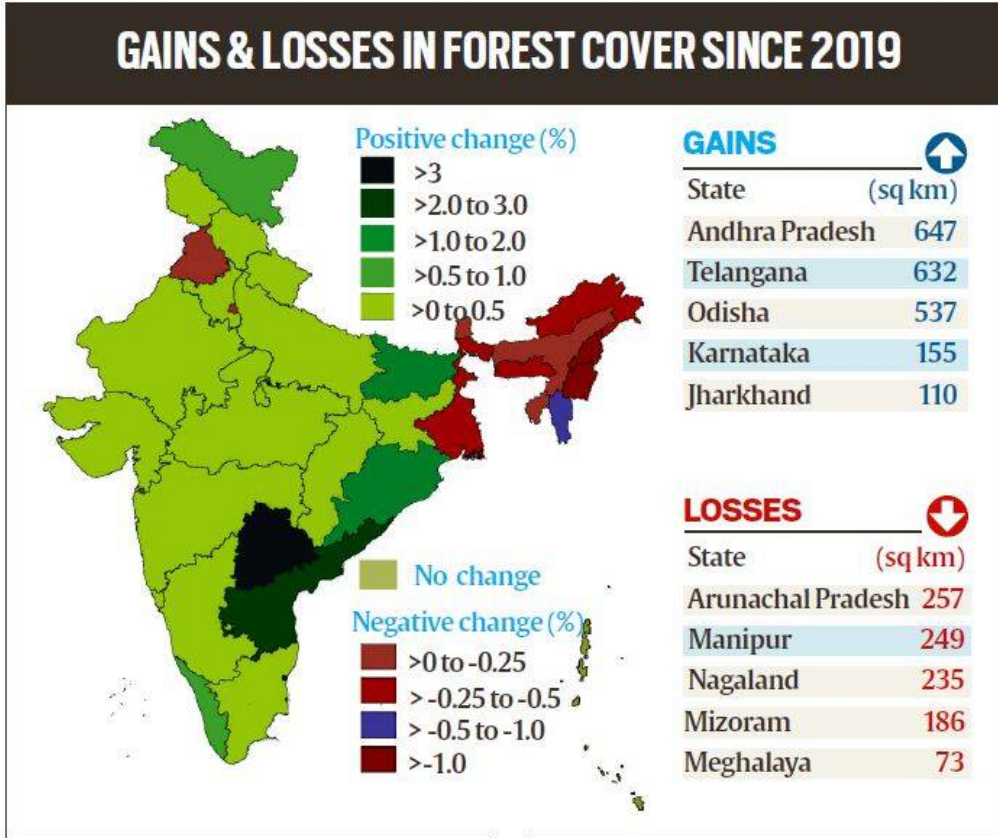
वनों का महत्त्व:

- वन पृथ्वी के एक-तहिई भू-कषेत्र को कवर करते हैं तथा वभिन्न पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें जल वजिज्ञान चक्र के संतुलन को बनाए रखने, जलवायु वनिथिमान में योगदान और जैव वविधिता के संरक्षण में उनकी प्राथमिक भूमिका शामिल है ।
- पारस्थितिकि दृष्टिकोण के अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन का भी यह नषिकर्ष नकालता है कि वन संसाधन देश के आर्थिक वकिस में योगदान कर सकते हैं और इसलिये वभिन्न कृषि एवं वानिकी से संबंघति गतिविधियों के लिये वन आवरण को बनाए रखना आवश्यक है ।
 - वन कई लोगों की आजीविका का समर्थन करते हुए 86 मिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करते हैं ।
- पृथ्वी पर हर कसिी का जंगलों से कसिी-न-कसिी रूप में संपर्क रहा है । इसमें ऐसे समुदाय शामिल हैं जो अपने जीवन और आजीविका के लिये प्रत्यक्ष तौर पर इन पारस्थितिकि तंत्रों पर नरिभर हैं या ऐसे समुदाय जो इन जंगलों से प्राप्त उत्पादों पर नरिभर हैं ।
- वनों का सतत प्रबंधन और संसाधनों का उपयोग [जलवायु परविरतन](#) को रोकने तथा वर्तमान एवं भवष्य की पीढ़ियों की समृद्धि व कल्याण में योगदान देने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं । वन गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं ।
 - इन अमूल्य पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों के बावजूद वैश्विक स्तर पर [वनों की कटाई](#) खतरनाक दर से जारी है ।
 - 'संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन' का अनुमान है कि वर्ष 2015 और वर्ष 2020 के बीच वशिव स्तर पर प्रत्येक पाँच वर्ष में 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि को साफ किया गया । 'ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच' के अनुसार, भारत ने अकेले वर्ष 2020 में प्राकृतिक वन का 132 हेक्टेयर कषेत्र खो दिया ।
 - एक अन्य अध्ययन के अनुसार, [अमेज़न](#) के जंगलों ने कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को अवशोषित करने के बजाय इसका उत्सर्जन करना

शुरू कर दिया है।

भारत में वनों की स्थिति

- **भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021** के अनुसार, देश में मुक्त श्रेणी में 3,07,120 वर्ग किलोमीटर जंगल हैं, जिसमें पिछले दो वर्षों (2019-21) में 4,203 वर्ग कमी. की वृद्धि हुई है।
- इसमें स्क्रब लैंड (46,539 वर्ग कमी.) को शामिल करें तो यह कुल 3,53,659 वर्ग कमी. हो जाता है जो भारत में 10.76% अवक्रमित वन और स्क्रब लैंड का गठन करता है। यह हिम केवल वन क्षेत्र पर विचार करें तो यह 43.03% है।
- रिपोर्ट ने देश भर में वनों के आवरण में नरिंतर वृद्धि प्रदर्शित की है लेकिन पूर्वोत्तर के वन आवरण में गतिवट तथा प्राकृतिक वनों का क्षरण जैसे कुछ अन्य पहलुओं को विशेषज्ञों ने चर्चा के प्रमुख कारणों के रूप में चिह्नित किया है।



वनों के लिये प्रमुख सरकारी पहल:

- **हरति भारत हेतु राष्ट्रीय मशिन:**
 - यह **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत आठ मशिनों में से एक है।
 - इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण व भोजन-पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP):**
 - इसे नमिनीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये वर्ष 2000 से लागू किया गया है।
 - इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **क्षत्पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA Funds):**
 - इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है, जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है।
 - इस धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों के पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन, प्रशिक्षण व जागरूकता पैदा करने, लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।
- **नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेज़र्टफिकेशन:**
 - इसे वर्ष 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार किया गया था।
 - इसका कार्यान्वयन MoEFCC द्वारा किया जाता है।
- **वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (एफएफपीएम):**

◦ यह केंद्र द्वारा वनितपोषति एकमात्र कार्यक्रम है जो वशिष रूप से जंगल की आग से नपिटने में राज्यों की सहायता के लयि समरपति है ।

वगित वर्षों के प्रश्नः

प्रश्न. नमिनलखिति राज्यों पर वचिार कीजयिः (2019)

1. छत्तीसगढ
2. मध्य प्रदेश
3. महाराष्ट्र
4. उड़ीसा

ऊपर वर्णति राज्यों में कुल क्षेत्रफल के वनावरण प्रतशित के संदर्भ में राज्यों का नमिनलखिति में से कौन-सा आरोही क्रम सही है?

- (a) 2-3-1-4
- (b) 2-3-4-1
- (c) 3-2-4-1
- (d) 3-2-1-4

उत्तरः (c)

स्रोतः डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-day-of-forests>

